प्रदेश में सोमवार को करोना संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई

राज्य में सोमवार को 9480 नए संक्रमित मिले, जबकि रविवार को 14112 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सोमवार को करोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। इस दौरान राज्य में 9480 नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि इसके पीछे करोना की जांचें कम होना बताया जा रहा है। इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 23 और लोगों की मौत हो गई है।

प्रदेश में सोमवार को 22 हजार 376 जांचों पर 9480 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इससे रविवार को 60 हजार 726 जांचों पर 14112 रोगी मिले थे। जांच कम होने के कारण राज्य में एक ही दिन में 4632 और जयपुर में 1242 मरीजों कम मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को सरकारी अस्पतालों के सुबह 9 से 11 बजे तक ही खुले रहने के कारण मात्र दो घंटे ही सैम्पल लिए जाते हैं। इस कारण रविवार को सैम्पलिंग कम होने से अगले दिन संक्रमितों की

- **संक्रमितों की संख्या में कमी आने के पीछे जांचे कम होना बताया जा रहा है। इस दौरान पिछले चौबीस घंटों केवल 22 हजार जांचे ही की गई।**
- **राजधानी जयपुर में 2424 नए संक्रमित मिले हैं।**
- **इस बीच, प्रदेश में करोना से 23 और लोगों की मौत हो गई है।**

संख्या में कमी आ जाती है। बाकी अन्य कार्य दिवस में पूरे समय अस्पतालों के खुलने से दिनभर सैम्पल लिए जाते हैं।

इधर राजधानी जयपुर में भी सोमवार को नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। इस दौरान जिले में 2424 नए रोगी पाए गए हैं। इसके अलावा अलवर में 754, जोधपुर में 621, डूंगरपुर में 488, उदयपुर में 457, चित्तौड़गढ़ में 394, अजमेर में 391, हनुमानगढ़ में 359, भीलवाड़ा में 353, सीकर में 311, कोटा में 283, पाली में 251, बांसवाड़ा में 237, झालावाड़ में 206, बीकानेर में 200, प्रतापगढ़ में 183, भरतपुर में 142, झुंझुनूं में 132, बारां व बाड़मेर में 130-130, धौलपुर में 125, राजसमंद में 118, सिरोही में 108, सवाई माधोपुर में 107, नागौर में 103, करौली में 97, गंगानगर में 92, टोंक में 77, दौसा में 64, बूंदी में 43, जालौर में 41, जैसलमेर में 32 और चूरू में 27 नए संक्रमित मिले हैं।

इधर राज्य में सोमवार को करोना से 23 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 5 जोधपुर में और 4 लोगों की मौत जयपुर में हुई है। इसके अलावा बीकानेर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में 2-2 तथा टोंक, सीकर, पाली, करौली, जालौर, गंगानगर, धौलपुर व अजमेर में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 9118 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 9397 और मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक करोना से 10 लाख 36 हजार 762 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालाकि अभी 93 हजार 502 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 24736 मरीज जयपुर में मौजूद है। इसके अलावा इसके अलावा अलवर में 7384, जोधपुर में 7215, उदयपुर में 4580, भरतपुर में 4198, कोटा में 3627, अजमेर में 3603, पाली में 3217, चित्तौड़गढ़ में 2746, भीलवाड़ा में 2624, सीकर 2512, बीकानेर में 2260, हनुमानगढ़ में 2236, डूंगरपुर में 2211 और बाड़मेर में 2166 तथा शेष जिलों में इससे कम मरीज हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में एसीबी की अहम भूमिका : सीएम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को उनके निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीबी के कामकाज की समीक्षा की।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए एसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसीबी को स्टाफ एवं तकनीकी संसाधनों से सुदृढ बनाने के साथ ही पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है, ताकि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की राज्य सरकार की नीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में एसीबी और मजबूती से काम करे।

गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीबी के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। गहलोत ने एसीबी की पिछली समीक्षा बैठक में दिये गए निर्देशों की

- **मुख्यमंत्री ने एसीबी अधिकारियों से उनके अनुभव पूछे एवं सुझाव भी सुने**

पालना जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, उन्होंने भ्रष्ट कार्मिकों एवं संगहित भ्रष्टाचार के खिलाफ भी प्रभावी एक्शन लेने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बात की, उनके अनुभव पूछे एवं विभाग की बेहतरी के संबंध में सुझाव भी सुने। उन्होंने एसीबी हैल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

एसीबी के महानिदेशक बी.एल. सोनी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के 90 प्रतिशत मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है, इससे राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस अगेन्स्ट करप्शन नीति को मजबूती मिली है।

बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अति. मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमन्त गेरा, एडीजी एसीबी दिनेश एमएन, एसीबी मुख्यालय से डीआईजी सवाई सिंह गोदारा एवं डॉ. विष्णुकांत, अजमेर रेंज के डीआईजी (एसीबी) समीर कुमार सिंह, जोधपुर रेंज के डीआईजी (एसीबी) कैलाश विश्नोई सहित विभिन्न रेंज एवं जिलों में पदस्थापित एसीबी अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए।

कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया भर्तियों का कैलेंडर

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को इस वर्ष की भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। इस वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक 11 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।

कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव पुष्कर राज शर्मा ने बताया कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 7, 8 और 9 मई को होगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा मई में होगी, जबकि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की परीक्षा मई और जून में करवाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती की परीक्षा 4 जून को, कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 18-19 जून को, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा जुलाई में, तहसील राजस्व लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा सितंबर में होंगी।

12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन आज

जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में वर्चुअल आयोजित किया जायेगा। गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेमसिंह मेहरा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्चुअल कार्यक्रम में राज्यपाल राजभवन से, विशिष्ट अतिथि निर्वाचन विभाग के स्टेट आइकन शताब्दी अवस्थी एवं सुंदर सिंह गुर्जर जुड़ेंगे।

रोड़ा एक्ट संशोधन संबंधी विधेयक पास करवाने के लिये सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन घेराव का ऐलान कर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

उत्तरप्रदेश में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी : माथुर

जयपुर। भाजपा सांसद ओमप्रकाश माथुर के जयपुर दौरे के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात माना जा रहा है। वही राजनैतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात के बाद माथुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी आता हूं तो पुराने कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम होता है। तिवाड़ी से मेरा औपचारिक मिलन था कोई खास बात नहीं है।

भाजपा के वेटिंग मुख्यमंत्री जैसे सवाल पर बोले माथुर ने कहा कि सारे निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। माथुर ने कहा कि 48 साल से राजस्थान में काम कर रहा हूँ। मेरे दौरे स्वाभाविक होते हैं। माथुर ने कहा कि उत्तरप्रदेश में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा सरकार में पिछले 5 साल में जो काम हुआ है। उसका लाभ उत्तरप्रदेश को मिलेगा। आम मतदाता तक प्रधानमंत्री की योजना पहुँची है।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था, अशोक गहलोत का साथ छोड़ दे, लेकिन मैंने मना कर दिया : गुढ़ा

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में सियासी उठापटक पुराना हो चुका है और मंत्रिमंडल फेरबदल भी हो चुका है लेकिन गाहे-बगाहे कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों से तो कभी अन्य नेताओं के बयानों से सियासी उठापटक की यादें फिर ताजा हो जाती है अब राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के ताजा बयान के बाद राज्य की सियासी उठापटक की यादें फिर ताजा हो गई है। राजस्थान के हाल ही मंत्री बने राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बार

- **मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपने बयान से सियासी उठापटक की यादें फिर ताजा कीं**

फिर सियासी उठापटक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए हैं।

अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि जब प्रदेश में सियासी उठापटक चल रही थी, तब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनसे कहा था कि वह अशोक गहलोत का साथ छोड़ दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने उदयपुरवाटी क्षेत्र के गुढ़ा ढहर गांव में पंचायत भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि काम करने के लिए मैंने मेरे समाज के बड़े-बड़े नेताओं को छोड़ दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुझे कहा था, उस समय सरकार की उठापटक चल रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं राजपूत समाज का आदमी हूं। मैं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हूं, आप अशोक गहलोत को छोड़ दो।

गुढ़ा ने कहा कि ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैंने कहा मैं जाति नहीं देखता हूं, काम देखता हूं। अशोक गहलोत जैसा कोई नहीं है। नेता की जाति नहीं देखनी चाहिए। नेता का तो कौम और व्यक्तित्व देखना चाहिए। गुढ़ा ने कहा कि राजपूत समाज ने उदयपुरवाटी में हमेशा सैनी समाज का साथ दिया है।

प्रदेश भर के सोनोग्राफी सेंटर्स का नियमित निरीक्षण किया जाएगा

जयपुर, (का.सं.)। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और कन्या भ्रूण लिंग जांच के अवैध परीक्षण को रोकने के लिए प्रदेशभर के सोनोग्राफी सेंटर्स का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर पर अंतरजिला और प्रदेश स्तर पर कमेटी बनाकर सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया जाए ताकि भ्रूण हत्या पर अंकुश लग सके।

मीणा सोमवार को बालिका दिवस पर स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा आयोजित पीसीपीएनडीटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिकॉय ऑपरेशन के दौरान दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि लोगों में डर बना रहे और वे किसी भी भ्रूण लिंग की जांच करने से डरें। उन्होंने कहा कि हालांकि पीसीपीएनडीटी सेल द्वारा प्रदेश में

- **चिकित्सा मंत्री ने ली पीसीपीएनडीटी की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश**
- **भ्रूण लिंग जांच को अभियान बनाकर आमजन को जागरूक करने के दिए निर्देश**

बेहतर कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश का महिला लिंगानुपात जो 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 900 था वहीं अब बढ़कर 945 हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थानों तक वितरण के लिए जागरूकता पोस्टर एवं फोल्डर का विमोचन भी किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वाले मुखबिर को राशि बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। आमजन बिना किसी भय और दबाव के सूचना दे सकता है। उन्होंने इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन व प्रभावी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों द्वारा सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण नहीं करने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

चिकित्सा सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर ने सोनोग्राफी सेंटर्स पर सोनोलॉजिस्ट के नियमित प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। वर्तमान में प्रदेश की छह मेडिकल कॉलेजों पर ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी दिनों में प्रशिक्षण सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने सोनोग्राफी सेंटर्स पर मिले डाटा का विश्लेषण कर प्रभावी कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।

अधिक अंक लाने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 में अधिक अंक लाने के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने के मामले में शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश नेहा सक्सेना की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने इतिहास विषय के स्कूल व्याख्याता के 1968 पदों के लिए 16 अक्टूबर 2015 को भर्ती निकाली थी। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम जारी कर कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी। इसके बाद आयोग ने परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया। जिसमें याचिकाकर्ता ने 247.7 अंक हासिल किए। याचिका में कहा गया कि भर्ती में याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले दूसरे अभ्यर्थियों को परीक्षा के पहले परिणाम के बाद नियुक्ति दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता के अधिक अंक होने के बावजूद से नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि आयोग की यह कार्य प्रणाली संविधान के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के खिलाफ है। इसके अलावा नियमानुसार आयोग उच्च मेरिट को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आयोग ने पहले परिणाम में छोड़ी गलतियों के चलते संशोधित परिणाम जारी किया था और उसमें याचिकाकर्ता के अंक बढ़ गए। ऐसे में उसे पूर्व में अन्य अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति के समान नियुक्ति और अन्य परिलाभ दिए जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मंत्री पद से हटाए गए तीनों नेताओं को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा

जयपुर, (का.प्र.)। प्रदेश की गहलोत सरकार ने कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा बढ़ाते हुए तीन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गुजरात प्रभारी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पंजाब प्रभारी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। यह तीनों नेता हाल ही मंत्री पद से हटाए गए हैं। इनमें से हरीश चौधरी और रघु शर्मा जहां पंजाब और गुजरात के प्रभारी बनाए जा चुके हैं, वहीं गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में इन तीन कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा वाई श्रेणी करने का निर्णय किया गया। इसी के साथ अब कांग्रेस के 6 नेताओं को वाई वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलने लगेगी। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार तीन विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे चुकी है। गृह विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी को सशस्त्र एस्कॉर्ट भी मिलेंगे। वैसे तो नेताओं पर संभावित खतरे और उन्हें किसी तरह की मिल रही धमकियों सहित अन्य कुछ जरूरी बातों को देखते हुए यह सुरक्षा दी जाती है। या फिर गृह विभाग के पास

- **हरीश चौधरी, रघु शर्मा और डोटासरा को गृह विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने दी सुरक्षा, इससे पहले कृष्णा पूनिया, हुड़ला और अवाना को भी मिल चुकी है यह सुरक्षा**
- **तीनों नेताओं को बाहरी राज्यों में दौरे के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से दी गई है वाई श्रेणी**

इस तरह के कोई प्रस्ताव आते हैं तो उन्हें सरकार गुण-अवगुण के आधार पर मंजूरी देती है। इन तीनों नेताओं को गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार दूसरे राज्यों के दौरों के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है।

इसी बैठक में कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश माथुर की वीआईपी सुरक्षा को यथावत रखा है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा यथावत जारी रहेगी। इनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गुजरात प्रभारी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पंजाब प्रभारी और पूर्वमंत्री हरीश चौधरी को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय किया है। डोटासरा, हरीश चौधरी को सशस्त्र एस्कॉर्ट भी मिलेंगे।

वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वीआईपी लोगों को दी जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 1 या कभी-कभी 2 कंमाडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। नेताओं को किसी चुनावी दौरे के लिए बाहर जाने या किसी भी तरह की खतरे की आशंका को देखते हुए दी जाती है।

प्रदेश में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। जेड सुरक्षा श्रेणी के तहत करीब 22 सुरक्षाकर्मी और दो एस्कॉर्ट गाड़िया मिलती हैं। सुरक्षाकर्मी मशीनगन और अत्याधुनिक संचार के माध्यमों से लैस होते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश माथुर की वीआईपी सुरक्षा दी हुई है। साथ ही महुआ विधायक ओमप्रकाश हुडला, कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया और नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है।

अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना नोटिस

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद कनिष्ठ अभियंता को एईएन पद पर पदोन्नत नहीं करने पर प्रमुख पीएचईडी सचिव सुधांश पंत और चीफ इंजीनियर राकेश बुहाडिया को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश उर्वशी दीक्षित व अन्य की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत वर्ष 26 अगस्त को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं की बीटेक की डिग्री की उनकी सर्विस बुक में एंट्री करते हुए उन्हें एईएन पद पर पदोन्नति दी जाए।

बालिकाएं अवनि जैसे देश और विश्व में अपना नाम रोशन करें : भूपेश

जयपुर, (का.सं.)। महिला अधिकारिता निदेशालय की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जेएलएन मार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में करोना प्रोटोकोल की पालना करते हुए राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कहा कि हम चाहते है कि आने वाले समय में बालिकाएं ऊँचे पदों को सुशोभित करें एवं देश व विश्वभर में अवनि के जैसे अपना नाम रोशन करें और राजस्थान की बेटियां एक मिसाल कायम करें। उन्होंने कहा कि राज्य में

- **राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम**

लिंगानुपात पिछले वर्षों में लगातार सुधार हुआ है वहीं बाल विवाह में भी कमी आई है। प्रदेश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नित नएं कीर्तीमान रच रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना शुरू की है जो राजस्थान का नवाचार है। राज्य में करवाये गए सर्वे से पता चला कि बड़ी संख्या में महिलाएं माहवारी की स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बीमार हो रही है और गंभीर रोगों से ग्रसित हो रही है। उन्होंने लोगों से आहवान किया कि उड़ान योजना से सब जुड़ें और एक स्वस्थ नारी का एक सशक्त बालिका का संकल्प लें। अगर हमारी बालिकाएं स्वस्थ और सशक्त होगी तो आने वाला राजस्थान का कल भी सशक्त होगा। महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को ध्यान में रखते हुए आई एम शक्ति उड़ान योजना सरकार लेकर आयी है जिसके अन्तर्गत निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घूंघट प्रथा का त्याग कर महिलाओं को आगे आना होगा।

प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा महिला एवं बाल विकास द्वारा संबोधन कहा कि बालिकाओं के विकास और सशक्तिकरण से प्रदेश का विकास होगा। राज्य सरकार इस हेतु प्रतिबद्ध है।

बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं का हो रहा है विकास: मुख्य सचिव

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बायोमास नीति-2010 जारी की थी। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के तहत बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है साथ ही उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्य सोमवार को यहां शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएसएलईसी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का गठन सैद्धांतिक रुप से स्वीकृत बायोमास आधारित विद्युत परियोजना के लिए किया गया है।

आरआरईसी के निदेशक एन.एस. निर्वाण ने बताया कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बायोमास नीति के तहत प्रस्तावित तीनों प्रोजेक्टस मैसर्स वीसीए पावर प्राईवेट लिमिटेड (14.90 मेगावॉट) ग्राम धोद, सीकर, मैसर्स टीएनए रिन्युएबल इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (14.90 मेगावॉट) ग्राम डूगराना तहसील भादरा, हनुमानगढ़ एवं मैसर्स नैनो इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (8 मेगावॉट) ग्राम शैतानसिंह तहसिल लोहावट, जोधपुर को अनुमोदित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फर्मों को प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये 36 माह का समय दिया गया है। निर्वाण ने बताया कि उक्त फर्मों ने भूमि कर, पावर इवेक्यूएशन अप्रूवल एवं पानी की एनओसी प्राप्त कर ली है। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा क्रय की जायेगी। इसके लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम फर्मो के साथ पावर परचेज एग्रीमेन्ट करेगा। उन्होंने बताया कि बायोमास आधारित विद्युत परियोजना में सरसों की भूसी, कचरा एवं कृषि अवशेषों को काम में लिया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते है। वर्चुअल बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक भास्कर आत्माराम सावंत, जल संसाधन विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी राज, जिला कलेक्टर जोधपुर हिमांशु गुप्ता, जिला कलेक्टर सीकर अविचल चतुर्वेदी एवं जिला कलेक्टर हनुमानगढ नथमल डिडेल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपथित थे।

एनटीटी कोर्स की योग्यता का ब्यौरा दे राज्य सरकार : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती-2018 में एनटीटी कोर्स वालों की योग्यता से जुड़े मामले में एएजी शीतल मिर्धा से यह बताने के लिए कहा है कि राज्य सरकार ने किस आधार पर एनटीटी कोर्स की योग्यता तय की थी। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को इससे जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिया। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि 2010 तक प्रदेश में 27 संस्थानों को एनटीटी कोर्स चलाने के लिए मंजूरी दे रखी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटीई को 30 मार्च 2010 को सूचित कर दिया था कि राज्य सरकार ने 2010-2011 से एनटीटी कोर्स को चलाने का निर्णय नहीं लिया है और जिन संस्थानों को कोर्स चलाने की मंजूरी दे रखी थी उसे वापस ले लिया है। इसके साथ ही कहा गया राज्य सरकार ने बाद में प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए एनटीटी योग्यता रखने के लिए नीतिगत निर्णय लिया था। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट के सामने आया कि एनसीटीई के अनुसार एनटीटी कोर्स प्रदेश में 2002 के बाद से बंद था, लेकिन एएजी ने कहा कि राजस्थान में एनटीटी कोर्स 2010 तक संचालित हुआ था। जिस पर अदालत ने उन्हें इस अवधि में एनटीटी कोर्स चलाने वाले संस्थानों की जानकारी देने के लिए कहा था।